FEBRUARY 2011

The Hindu, Monday, February 14, 2011

Centre evolves new educational methodology for rural development

New Delhi: To ensure power use of its Rs.86,553 crore annual rural spending, an ambitious curriculum to train and educate all those involved in the execution of the programmes concerned is on the anvil. This mass-based decentralized capacity building process, the first of its kind among developing countries, intends to develop skills of 40 lakh hands annually.

To achieve this, the Centre has evolved a new educational and training methodology for rural development and improving the livelihoods of the rural folk under a Central Training Authority to be set up under a new law currently under consideration.

The Union Ministry of Rural Development has come up with the draft National rural Development Training Authorities Bill, 2011 which has been received the approval of both the Law Ministry and Expenditure Ministry. It has been circulated for public opinion before its introduction in Parliament for ratification.

Restructure of Process:

entire training and educational process will be restructured so as to address shortcomings pointed out by both the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and Planning Commission. The two bodies have expressed concern that such a large sum was being spent through people who were not properly trained and help poor capacity as a factor for the poor outcome in the rural sector.

Consequently, it has been recommended under the proposed law that at least one percent of the budget allocation for the rural sector should be earmarked for training and educational activities. In the present context, it works out to an expenditure of about Rs.865 crore annually.

All the 30 lakh panchayat members, 45 lakh government functionaries, members of the slef help groups (SHGs), and 40 lakh Bharat Nirman volunteers will be trained under the new structure, which means 2 crore people need to be brought under the process. With the panchayat elections being held every five years, besides the changing composition of the other groups, the proposed process calls for continuity.

It will be the responsibility of the authority to develop the academic and knowledge generation architecture and establish different “schools” covering all aspects of rural development and improving rural livelihoods.

The Central Training Authority at the national level will function under te chairmanship of the Union Rural Development Minister and its function will be decentralized with similar structures right down to the block level.

The National Institute of Rural Development, Hyderabad, will be converted as the Central Training Authority which will have two vice chairpersons, members drawn from central ministries, Planning commission and State governments, academicians, seven legislators from across the State, two Lok Sabha members and a Rajya Sabha member, Chairman University Grants Commission, three vice-chancellors, including that of IGNOU. Its headquarters will be Hyderabad.

The Pioneer, Thursday, February 24, 2011

First of a kind: 'farm Budget' by Yeddyurappa

Bangalore: In what is said to be a first in the country, Karnatak Chief Minister BS Yeddyurappa will present an agricultural budget on February 24. Yeddurappa told The Pioneer that he would be presenting an exclusive agricultural budget to help crisis stricken agricultural sector.

He said, "I am presenting an exclusive agricultural budget to help the farming sector. My Government is planning to reduce the interest rates on the farming sector. It is a unique exercise."

The Chief Minister will also announce agricultural loans at just one per cent interest from the current three per cent to help curb the negative growth of the sector in the State.

Agricultural experts are worried over the sector showing a negative growth of 0.4 per cent, a trend prevalent for the past few years compared to the national GDP growth and welcome this separate budget to aid farming sector. The experts are of the opinion that the Chief Minister, apart from bringing down the interest rates to one per cent on the farming loan, will be expected to announce sops to help the farming sector.
Professor RS Deshpande, Director of the Institute of Social and Economic Change (ISEC), a premiere research institute in the country, has welcomes the exclusive agricultural budget being presented by the Government.

He said, "This is a very good initiative by the Government. This is very unique also in the country. We have to watch for new schemes that will boost farming sector in the State."

Talking to The Pioneer the chairman of Organic farming Mission, AS Anand has welcomes the concept of the agricultural budget and said the organic farming field would expect more from the Government to boost such farming in the State.

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। शनिवार • 5 फरवरी • 2011

'गांवों के विकास बगैर दिल्ली नहीं बन सकती पेरिस'

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली नगर निगम के बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष ने राजधानी को पेरिस बनाने के कांग्रेसी सरकार के दावे को हास्यास्पद बताया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि 40 लाख की आबादी उन अनधिकृत कालोनियों में रहती है, जहां कोई सुख सुविधा नहीं है। गांवों की स्थिति दयनीय है। गांवों के विकास के बगैर शहर के विकास की बात करना बेमानी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के जगदीश ममगांई ने कांग्रेस के पूर्व पार्षदों के नाम गिनाते हुए निगम के स्वर्णिम काल को कलंकित करने का आरोप लगाया। इस पर विपक्ष भड़क गया और हंगामा किया। विपक्ष ने महापौर पर अपने पार्षदों को अधिक समय बोलने देने का आरोप लगाया।

- निगम के बजट पर चर्चा के दौरान उठा गांवों के विकास का मुद्दा
- कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गांवों पर नहीं खर्ची गई एक पाई भी

बजट सत्र में शुक्रवार को तीसरे दिन की चर्चा के दौरान गांवों की दयनीय स्थिति को लेकर भाजपा पार्षद नारायण सिंह उबल पड़े। उन्होंने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से दिल्ली का विकास हुआ है, शहर और गांवों के बीच की दूरी बढ़ी है। आज स्थिति यह है कि गांवों में कहीं भी विकास नहीं दिखता। गांवों की सड़कें खस्ता हैं। आने-जाने का कोई सार्वजनिक साधन नहीं है। गांव में सर्कल रेट बढ़ाकर महंगाई बढ़ा दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गांवों में विकास पर एक पाई भी खर्च क्यों नहीं की गयी? सिंह ने कहा कि गांवों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। कांग्रेस के बुजुर्ग पार्षद मुकुंद दास भट्ट ने कहा कि पूरी कवायद दिल्ली के 33 फीसद इलाके के विकास को लेकर हो रही है। जबकि 66 फीसद दिल्ली पुरानी दिल्ली में बसती है। नगर निगम वहां कोई विकास नहीं करा रहा। गुस्से भरे लहजे में उन्होंने कहा कि निगम के कानून जनहित के नहीं हैं। एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दिल्ली नरक बन जायेगी। उन्होंने कहा कि निगम में काम करने वाले ए क्लास के ठेकेदार बन गये, जबकि निगम कंगाल होता गया।

निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगांई ने निगम में भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हुए कई कांग्रेसियों के नाम गिनाये, जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो निगम को कमजोर करने का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी ने 1975, 1980 और 1990 में यानी तीन बार निगम को भंग किया। ममगांई ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि केवल 10 फीसद दिल्ली का विकास होने से राजधानी पेरिस नहीं बन जायेगी। दिल्ली की अनधिकृत कालोनियां उन्हीं की सरकार की देन हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेसी पूर्व पार्षदों के नामों की चर्चा होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष जयकिशन शर्मा के कहने के बावजूद कांग्रेसी पार्षद नारेबाजी करते रहे। इसके चलते महापौर को 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। हरीश अवस्थी ने निगम अफसरों पर काम में बेवजह अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया।

कांग्रेसी पार्षद हेमचंद गोयल ने निगम को कमजोर करने के लिए भाजपा की तत्कालीन दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि निगम से जल विभाग भाजपा ने ही छीना था। विकास के नाम पर चार साल में भाजपा दिल्ली की सीमाओं पर गेट तक नहीं बना पायी। चंद्र करण त्यागी ने गांवों के विकास का मुद्दा उठाया। पार्षद नीलम बुद्धिराजा ने स्कूलों में सफाईकर्मी बढ़ाने की पैरवी की। ऊषा मेहता ने बजट को संतुलित बताया। राजपाल शौकीन, वीपी मंडल, डॉ भीम सिंह शर्मा, श्याम लाल, चौ. सुरेंद्र सिंह, मंजू गुप्ता, नफीसा खातून, सविता शर्मा आदि ने सुझाव दिये।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 24 फरवरी 2011

देश की प्राथमिकता है ग्रामीण विकास

कार्यक्रम

- राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के नए कैंपस का किया उद्घाटन
- जमीनी अनुभव के लिए स्थानीय स्तर पर काम करने पर जोर दिया

द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के नए भवन के उद्घाटन मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को स्मृति चिन्ह देते संस्थान के चेयरमैन सुनील शास्त्री। साथ में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित।

द्वारका, जागरण संवाददाता : द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के नए कैंपस का बुधवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यापार स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों को पंचायती राज संस्थाओं, किसानों, स्थानीय बुनकरों, कारीगरों और स्थानीय स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर काम करना चाहिए। जमीनी हकीकत मालूम होने के लिए यह जरूरी है। इस तरह नए प्रबंधन से ग्रामीणों को फायदा होगा और उनकी जरूरतों व समस्याओं से प्रबंधन संस्थान भी वाकिफ होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण विकास पर जोर देना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे भारतीय बाजार के आधार का विस्तार होगा और हमारे उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी। ग्रामीण भारत के उत्पादन, वित्त पोषण और विपणन की संभावनाओं के लिए नवीन दृष्टिकोण, विश्लेषण, नए समाधान और नए उपकरणों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि व्यापार ने एक अंतरराष्ट्रीय चरित्र ग्रहण कर लिया है। ई-वाणिज्य व्यापार अब वाणिज्य की एक स्वीकृत विद्या है। प्रबंधन पाठ्यक्रम वाणिज्य की नई तकनीक से छात्रों को परिचित होना चाहिए। भूमंडलीकृत दुनिया के इस युग में उद्यमों की भूमिका में वृद्धि हुई है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से बेहतर प्रबंधक बनकर विकसित देश के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इससे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नए भवन में लगाई गई लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री की विनम्रता और सादगी की चर्चा करते हुए उनके जीवन से युवा और संस्थान के छात्रों से सीख लेने का आग्रह किया। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन अनिल शास्त्री ने कहा कि यह संस्थान मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ पेशेवरों की नई पौध तैयार कर रहा है। यह पौध टीम में काम करने का अर्थ समझती है। शास्त्री का नारा 'जय जवान जय किसान' आज भी प्रासंगिक है, जो हमारे देश के हर कोने में प्रतिध्वनित है। इस मौके पर संस्थान के उप चेयरमैन जेपी अग्रवाल, निदेशक डॉ. केसी मिश्रा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।